## विचार बिन्दु

**अज्ञानी के लिए खामोशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं और यदि उसमे यह समझाने की बुद्धि हो तो वह अज्ञानी नहीं रहेगा। –शेख सादी**

# राजस्थान की पंच गौरव योजना: स्थानीय संसाधनों से वैश्विक पहचान तक

राजस्थान की पंच गौरव योजना राज्य के विकास के फलक पर एक अभिनव और दूरदर्शी पहल है जो स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान दिलाने, रोजगार सृजन करने और राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विकसित की गई है। यह योजना राज्य के प्रत्येक जिले की विशिष्टता को पहचान देकर उन्हें विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है। 17 दिसंबर 2024 को आयोजना विभाग द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम राजस्थान सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है और बजट 2025-26 में इस योजना को गति प्रदान करने के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना राजस्थान को भारत के मानचित्र में अलग स्थान देगी और राज्य को स्वदेशी, स्थानीय और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पंच गौरव योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के प्रत्येक जिले की पांच विशिष्ट पहचानों को चुनकर उन्हें विकास के मुख्य धारा में लाना है। प्रत्येक जिले से पांच तत्व या उत्पाद चुने गए हैं जिनमें एक उपज, एक प्रजाति, एक खेल, एक उत्पाद और एक पर्यटन स्थल शामिल है। कृषि विभाग एक उपज का चयन करता है, वन विभाग एक प्रजाति का, खेल विभाग एक खेल का, उद्योग विभाग एक उत्पाद का और पर्यटन विभाग एक पर्यटन स्थल का। यह पंचमुखी विकास मॉडल राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देता है और प्रत्येक जिले की विशिष्टता को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर रखता है।

स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान दिलाने में पंच गौरव योजना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के प्रत्येक जिले की अपनी विशिष्ट उपज, वनस्पति, खेल, हस्तशिल्प और पर्यटन स्थल हैं जो सदियों से उस जिले की पहचान बनकर रहे हैं। कोटा जिले का धनिया, खैर वृक्ष, कुश्ती, कोटा डोरिया और चंबल रिवर फ्रंट जैसे पंचगौरव इस जिले की विशिष्ट पहचान हैं। इन संसाधनों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए योजना के तहत विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है जिसमें मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ट्रेड शो और इंटरनेशनल एक्सपोजर शामिल हैं।

योजना के तहत प्रत्येक जिले के पंचगौरव को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखने के लिए विशेष अभियान शुरू किए गए हैं। इनमें जिले की विशिष्ट उपजों को विदेशी देशों में मार्केट किया जाएगा, हस्तशिल्प उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो में प्रदर्शित किया जाएगा और पर्यटन स्थलों को विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया जाएगा। इससे राजस्थान के स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी।

रोजगार सृजन में पंच गौरव योजना का महत्व अत्यंत विशिष्ट है। प्रत्येक जिले के पंचगौरव के विकास से कृषि, वन, खेल, उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। कृषि विभाग द्वारा चुने गए उपज के विकास से किसानों को नई तकनीक और मार्केटिंग के अवसर मिलेंगे जिससे उनके उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होगी। वन विभाग द्वारा चुने गए प्रजाति के संरक्षण और विकास से वन क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। खेल विभाग द्वारा चुने गए खेल के विकास से युवाओं को खेल क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उद्योग विभाग द्वारा चुने गए उत्पाद के विकास से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। पर्यटन विभाग द्वारा चुने गए पर्यटन स्थल के विकास से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के माध्यम मिलेंगे।

> **पंच गौरव योजना का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के पंचगौरव का विकास होगा और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर रखा जाएगा। इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य आत्मनिर्भर बन जाएगा।**

योजना के तहत युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए स्वर्ण अवसर प्रदान किए गए हैं। युवाओं को खेल क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे और उन्हें खेल प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अवसर दिए जाएंगे। किसानों को नई कृषि तकनीक और मार्केटिंग के अवसर मिलेंगे जिससे उनके उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होगी। महिलाओं को हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के विकास में रोजगार के अवसर मिलेंगे और उन्हें स्वरोजार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

''स्वदेशी, स्थानीय और आत्मनिर्भर'' की भावना को ठोस आधार प्रदान करने में पंच गौरव योजना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह योजना स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके स्थानीय उत्पादों को विकसित करने और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर रखने पर केंद्रित है। इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और राज्य आत्मनिर्भर बन जाएगा। योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अवसर दिए जाएंगे जिससे उनकी बिक्री में वृद्धि होगी और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्थान को भारत के मानचित्र में अलग स्थान देने में पंच गौरव योजना की भूमिका अत्यंत विशिष्ट है। यह योजना राज्य की विशिष्टता को राष्ट्रीय और वैश्लिक मंच पर रखती है और राज्य को विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित करती है। प्रत्येक जिले के पंचगौरव को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखने के लिए विशेष अभियान शुरू किए गए हैं जिससे राजस्थान को भारत के मानचित्र में अलग स्थान मिलेगा।

योजना के तहत राज्य की विशिष्ट उपजों, हस्तशिल्प उत्पादों और पर्यटन स्थलों को विदेशी देशों में मार्केट किया जाएगा जिससे राजस्थान को वैश्विक मंच पर पहचान मिलेगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी और राजस्थान को भारत के मानचित्र में अलग स्थान मिलेगा।

पंच गौरव योजना का कार्यान्वयन जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय समितियां प्रत्येक जिले के पंचगौरव का चयन और विकास कार्ययोजना बनाएंगी। राज्य स्तरीय समिति जिला स्तरीय प्रस्तावों और कार्ययोजनाओं का परीक्षण कर उन्हें अंतिम मंजूरी देगी। 8 सितंबर 2025 को राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई थी जिसमें जिला स्तरीय प्रस्तावों और कार्ययोजनाओं का परीक्षण कर उन्हें अंतिम मंजूरी दी गई थी।

योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न विभागों का सहयोग आवश्यक है। कृषि विभाग एक उपज के विकास में, वन विभाग एक प्रजाति के संरक्षण और विकास में, खेल विभाग एक खेल के विकास में, उद्योग विभाग एक उत्पाद के विकास में और पर्यटन विभाग एक पर्यटन स्थल के विकास में सहयोग देंगे। यह पंचमुखी विकास मॉडल राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देता है।

पंच गौरव योजना का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के पंचगौरव का विकास होगा और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर रखा जाएगा। इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य आत्मनिर्भर बन जाएगा। योजना के तहत युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए स्वर्ण अवसर प्रदान किए गए हैं जिससे राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।

योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार ने विस्तृत कार्ययोजना बनाई है जिसमें मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ट्रेड शो और इंटरनेशनल एक्सपोजर शामिल हैं। इससे राजस्थान के स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। पंच गौरव योजना राजस्थान के विकास के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है। यह योजना स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान दिलाने, रोजगार सृजन करने और राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

योजना के सफल कार्यान्वयन से राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे, और राज्य आत्मनिर्भर बन जाएगा। यह योजना राजस्थान के विकास के नए मॉडल को प्रस्तुत करती है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके स्थानीय उत्पादों को विकसित करने और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर रखने पर केंद्रित है।

पंच गौरव योजना राजस्थान के लिए एक नया अवसर है जो राज्य को विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। यह योजना स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान दिलाने, रोजगार सृजन करने और राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह योजना राजस्थान को भारत के मानचित्र में अलग स्थान देगी और राज्य को स्वदेशी, स्थानीय और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

**–अतिथि संपादक,**
**अविनाश जोशी,**
**वरिष्ठ पत्रकार एवं आर्थिक सलाहकार**

# नए और सशक्त भारत का उदय

## नरेन्द्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक 12 वर्ष

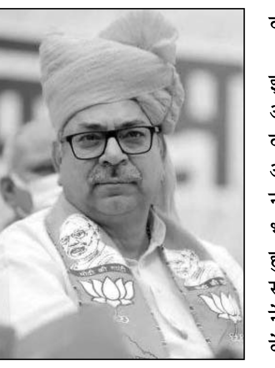

**डॉ. सतीश पूनियां**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले बारह वर्षों में भारत ने एक विकसित, आत्मविश्वास से लबरेज और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले मजबूत राष्ट्र के रूप में पहचान कायम की है। भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान की गाथाएं दुनिया की जुबान पर है। अब वह दौर नहीं रहा, जब आतंक फैलाने वाले मुल्क को देश में आतंकी घटनाओं में उसकी स्पष्ट संलिप्तता के बावजूद भी उसे दंडित करने के स्थान पर उसको डोजियर पर डोजियर सौंपा जाए, अब सीधी और स्पष्ट कार्रवाई होती है। यह सब संभव हुआ है एक कुशल, विजनरी और राष्ट्र प्रथम की भावना वाले नेतृत्व के कारण।

मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार यह जानती थी कि दुनिया के सामने खड़ा होना है तो हमें पहले आर्थिक ताकत बनना होगा। भारतीय नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त करना होगा। पिछले बारह वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था और देश के नागरिकों को सशक्त करने का काम किया है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की आग से झुलस रही है, उस दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7 की उत्साहजनक वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ रही है। ये आंकड़े ही साफ संकेत देते हैं कि देश के नागरिकों और दुनिया के निवेशकों का भरोसा मोदी सरकार पर लगातार बना हुआ है। वर्ष 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास मूलमंत्र के साथ काम आरंभ किया। इसका परिणाम आज देश के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने देश के सामाजिक और आर्थिक भूगोल को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। एक वक्त था जब लोग बैंक में खाता खुलवाने में हिचकते थे। लेकिन जनधन योजना ने देश के पूरे माइंड सैटअप को बदल दिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने बैंकों को खुद लोगों तक पहुंचा दिया। कभी देश की आधी से अधिक आबादी औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से कटी हुई थी। मोदी सरकार ने इस खाई को पाटने के लिए मिशन मोड में काम किया और आज 58 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में आज की तारीख तक तीन लाख करोड़ से अधिक की धनराशि जमा है।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को एक विजन दिया। उन्होंने युवाओं से रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनने का आव्हान किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से उनको सपनों को पंख दिये। उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा किया। आज गांवों शहरों में मुद्रा योजना के माध्यम से हजारों लाखों की संख्या में युवक और युवतियां स्वरोजगार के माध्यम हजारों हाथों को काम दे रहे हैं। आंकड़े खुद इस योजना की सफलता की गवाही देते हैं। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 57 करोड़ से अधिक मुद्रा ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे छोटे उद्यमियों के हाथों में सौंपी गई है। इसमें लगभग 68 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं और समाज के पिछड़े तबके से हैं। महंगी दवाओं और ईलाज को आसान बनाते हुए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा को बिलकुल किफायती बना दिया गया है। देशभर में खुले हज़ारों जन औषधि केंद्रों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं बाज़ार मूल्य से पचास से नब्बे प्रतिशत तक कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने पिछले बारह वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गति और कवरेज में क्रांतिकारी बदलाव किया है। इन वर्षों में ग्रामीण कनेक्टिविटी को अभूतपूर्व गति देते हुए सात लाख किलोमीटर से अधिक लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। इसका असर यह हुआ है कि इन बारहमासी सड़कों ने न केवल किसानों की फसलों को मंडियों तक आसानी से पहुँचाया है, बल्कि ग्रामीण अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को भी सुलभ किया है।

जल जीवन मिशन के माध्यम से महिलाओं सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की और इसे एक जन-आंदोलन बना दिया। ग्रामीण इलाकों में पाइप से पानी का दायरा आज बढ़कर पंद्रह करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच चुका है। इस योजना ने ग्रामीण भारत, विशेषकर महिलाओं को पानी से होने वाली गंभीर बीमारियों से मुक्ति दी है।

महिला सशक्तिकरण के साथ यह योजना ईज ऑफ लिविंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। कोविड महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया थम गई थी। लोग घरों में कैद हो गए थे। लोगों के सामने भूखो मरने की नौबत आ गई थी, उस दौर में मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा न सोए। सौभाग्य से उस वक्त राजस्थान प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष होने के नाते हमने प्रधानमंत्रीजी के निर्देशन में प्रदेश में यह सुनिश्चित किया कि पार्टी की तरफ से लोगों तक अधिक से अधिक सहायता पहुंचायी जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन की यह व्यवस्था आज भी अनवरत जारी है। देश के 81 करोड़ से अधिक नागरिकों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है।

हर सर पर छत के मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अब तक चार करोड़ से अधिक पक्के घरों का निर्माण किया गया और उन्हें गरीब और बेघर परिवारों को सौंपा जा चुका है। हाल ही में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना के अगले चरण को भी मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया यह पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियों ने भारत से गरीबी उन्मूलन के कार्य को एक अभूतपूर्व गति दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आवास और स्वच्छता के मोर्चे पर चौतरफा सुधार के कारण पिछले एक दशक में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी के जाल से बाहर आए हैं।

पाठकों को याद होगा कि 2014 से पहले स्वच्छता भारत की प्राथमिकताओं में कहीं पीछे छूट गई थी। लेकिन जब लाल किले से जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन का आव्हान किया। देशभर में रिकॉर्ड समय के भीतर 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया, जिससे ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर अब शत-प्रतिशत हो चुका है। यह केवल एक स्वच्छता अभियान नहीं था, बल्कि यह देश की करोड़ों महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और स्वास्थ्य से जुड़ा एक ऐतिहासिक सामाजिक सुधार आंदोलन था। देश के श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने ई-श्रम पोर्टल और विभिन्न पेंशन तथा बीमा योजनाओं के माध्यम से उनको संरक्षण देने की पहल की। आज देश के 31 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल हो चुके हैं। मोदी सरकार ने इन 12 वर्षों में देश की राजनीति के व्याकरण को बदल दिया है। 2014 से पहले की राजनीति महज जातिगत समीकरणों, तुष्टिकरण और वोटबैंक के इर्द-गिर्द घूमती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की राजनीति की एक नई संस्कृति विकसित की है। आज का भारत एक आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, जो अपनी कमियों को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है।

**–डॉ. सतीश पूनियां,**
**( हरियाणा भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद )**

# कैसे मिलें ईमानदार, संवेदनशील और जनहित को समर्पित प्रशासक?

**राजेन्द्र भाणावत**

आप कोई भी समाचार पत्र उठा लें, प्रशासन की संवेदनहीनता के समाचार निरंतरता के साथ प्रकाशित हो रहे हैं। प्रशासक चाहे वे किसी भी विभाग के क्यों न हों, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पुलिस, खान, कर, परिवहन आदि। इन सब विभागों के मुखिया अधिकांशतया आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस या अन्य अखिल भारतीय और राज्य सेवा के अधिकारी होते हैं। यदि सरकार के कामकाज में संवेदनशीलता लानी है, तो ईमानदार प्रशासकों और लोक सेवकों की संख्या को बढ़ाना होगा। इस हेतु सरकार को महत्वपूर्ण आवश्यक कदम उठाने होंगे। इनके बिना संवेदनशील और ईमानदार प्रशासन की कल्पना, कोरी कल्पना ही बनी रहेगी।

पहले लोक सेवकों कि चयन प्रक्रिया को ही लें। इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की वर्तमान व्यवस्था, अभ्यर्थियों के विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी का ही आकलन करती है। यह सोच ही सही नहीं है कि भौतिकी, इतिहास, समाजशास्त्र या कानून जैसे विषयों में अच्छे अंक लाने वाला अच्छा अधिकारी सिद्ध होगा प्रीलिम्स और मैंस परीक्षा पार करने के बाद साक्षात्कार के दौरान भी 20 से 30 मिनट में किसी भी व्यक्ति के बारे में यह आकलन करना संभव नहीं हो सकता कि वह आने वाले 30-35 वर्षों तक किस प्रकार की मानसिकता के साथ काम करेगा? गत कुछ वर्षों से ऐसे संवेदनशील और ईमानदार अधिकारियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। कुछ दशक पूर्व तक संभवतया संवेदनशील अधिकारी मिल पाए थे, किंतु अब तो यह दुर्लभ सा हो गया है। विषय विशेषज्ञ और तकनीकी रूप से पारंगत अधिकारी की नीयत यदि अच्छी नहीं है तो वह कहीं अधिक नुकसान समाज को पहुंचा सकता है। आज हम ऐसा ही कुछ देख रहे हैं। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसका किसी सरकारी विभाग से वास्ता पड़ा हो, तो उसकी धारणा भी लगभग ऐसी ही होगी।

चयन की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली संभवतया सेना में अधिकारियों की भर्ती के लिए है। लगभग चार या पांच दिन तक अभ्यर्थियों को मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की सतत निगरानी में रखा जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार की स्थितियों से गुजरना पड़ता है। बनावटी तौर पर, कोई व्यक्ति 15-20 मिनट तक तो स्वयं को संवेदनशील सिद्ध कर भी दे, किंतु चार-पांच दिन तक लगातार ऐसा कर पाना उसके लिए संभव नहीं होता और उसके व्यक्तित्व के वास्तविक गुण स्पष्टतया प्रकट हो जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों को भी इस प्रकार की प्रणाली के आधार पर अपनी चयन प्रक्रिया को बिल्कुल बदलना होगा। प्रारंभ में इसे साक्षात्कार के स्तर पर लागू किया जा सकता है। बाद में इसे प्रीलिम्स और लिखित मुख्य परीक्षा के स्तर पर भी लागू किया जा सकता है। प्रश्न पत्र भी किसी विषय विशेष की जानकारी का मूल्यांकन करने के बजाय विभिन्न परिस्थितियों में उसका दृष्टिकोण क्या रहता है, उसका आकलन करने वाला हो सकता है। परिणामस्वरूप, कहीं अधिक उपयुक्त लोक सेवकों के चयन की संभावना रहेगी। किसी भी व्यक्ति को गणित, भौतिक शास्त्र, इतिहास या नागरिक शास्त्र में कितने अंक प्राप्त हुए, उससे यह निर्धारित नहीं होता कि कोई व्यक्ति जनहित के प्रति समर्पित प्रशासक सिद्ध होगा या नहीं। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या ऐसे अधिकारियों को मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि पसंद करेंगे? यदि देश को संविधान के प्रति प्रतिबद्ध, निष्ठावान, ईमानदार अधिकारियों की वास्तव में आवश्यकता है तो ऐसे ही अधिकारियों का चयन होना चाहिए। अधिकारियों के लिए निर्धारित गुण केवल जनप्रतिनिधियों की सुविधा के अनुसार ही तय नहीं किए जा सकते। देश के 150 करोड़ लोगों के हित को सर्वोपरि रखने वाले और उनके प्रति संवेदनशीलता रखने वाले अधिकारी का कोई विकल्प नहीं हो सकता।

सही चयन के पश्चात प्रशिक्षण व्यवस्था में भी बहुत बदलाव करना होगा। मसूरी, हैदराबाद और जयपुर स्थित प्रशिक्षण संस्थाओं में वर्तमान की तरह केवल विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान या जानकारी देने की अधिक आवश्यकता नहीं है। आजकल तकनीक के युग में किसी भी विषय की पूरी जानकारी, अधिकारी, अपने स्तर पर इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसे विषय वस्तु की जानकारी देना अथवा कानून के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देना, समय को व्यर्थ करना ही होगा। इसके बजाय उसे विख्यात प्रतिष्ठित, अनुभवी, संवेदनशील अधिकारियों के साथ खुले संवाद का अधिकतम अवसर देना चाहिए, जिससे वह ऐसे प्रशासकों की जीवन शैली और कार्य प्रणाली पर चर्चा करके उसे आत्मसात करने का प्रयास कर सके।

ऐसी बात नहीं है कि आज अच्छे प्रशासकों का नितांत अभाव हो। ऐसे प्रशासक और पुलिस अधिकारी एवं अन्य सेवाओं के अधिकारी अभी भी सेवा में उपलब्ध हैं या सेवा निवृत्त हैं, जो नवनियुक्त अधिकारियों के लिए रोल मॉडल का काम कर सकते हैं। बस करना यह है कि ऐसे अधिकारियों का चयन किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह और भेदभाव के बिना सही लोगों के द्वारा किया जाए। प्रशिक्षण के लिए प्रभावी तरीका, केस स्टडीज पर चर्चा करना है। केस स्टडीज जो वास्तविक हों और अच्छी तरह लिखी गई हों तो वे प्रशासकों में वांछित दक्षता विकसित करने के लिए काम आ सकती हैं। ऐसी केस स्टडीज को एकत्रित किया जाना चाहिए और उन पर किसी निष्णात प्रशिक्षक के माध्यम से प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। जब तक इस प्रकार का प्रशिक्षण केवल व्याख्यान आधारित रहेगा, तब तक उसका अधिक प्रभाव नहीं होगा। दुर्भाग्य से अधिकांश प्रशिक्षण संस्थानों में आजकल यही हो रहा है।

प्रशिक्षण में उन्हें आधुनिकतम तकनीक में पारंगत किया जा सकता है, किंतु उन्हें यह भी समझाया जाय कि तकनीक केवल साधन है, साध्य नहीं। सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में श्रेष्ठतम व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। जबकि राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकांशतया अधिकारियों को, अपवादों को छोड़कर, बतौर सजा लगाया जाता है। वास्तव में यह सजा इन अधिकारियों के बजाय उन्हें अधिक मिलती है जो इस अवधि में वहां प्रशिक्षण के लिए आते हैं। राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों में भी श्रेष्ठतम अधिकारियों को चयन के आधार पर, नियुक्त किया जाना आवश्यक है, ताकि वे प्रशिक्षणार्थियों में ऊर्जा और उत्साह का संचार कर सकें।

यह बात अधिकारियों के दिलों दिमाग में अच्छी तरह बिठाई जा सकती हैं कि उनकी प्रतिबद्धता केवल और केवल देश के लोगों के प्रति, संविधान के माध्यम से है। जिस स्टील फ्रेम की बात सरदार वल्लभभाई पटेल ने कही थी, उसकी आवश्यकता जितनी आज है, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। आज के अधिकारियों की रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली हो गई है। लगता है स्टील में जंग लग गया है। देश के चाहे आईएएस अधिकारी हों या आईपीएस अधिकारी, सब जिस प्रकार सत्ता के बदलते ही अपना रंग बदल लेते हैं, उसे देखकर गिरगिट भी शरमा जाए।यह चिंता का विषय है। सत्ताधारी दल, प्रजातंत्र में बदलते रहेंगे, किंतु स्थाई सेवा में नियुक्त अधिकारियों, विशेष कर उच्च सेवा के अधिकारियों को, अपने कार्य करने के तरीके को इस प्रकार संवेदनशील और निष्पक्ष रखना होगा जैसी उनसे सरदार पटेल ने अपेक्षा की थी। तब ही, वे अपनी सेवा के प्रति एवं जनता के प्रति न्याय कर पाएंगे। एक और बड़ा कारण जो अधिकारियों को ईमानदारी और संवेदनशीलता के मार्ग से दूर करता है, वह है जवाब देही का नितांत अभाव। भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई एक-दो दिन की हेडलाइंस बनती है लेकिन कुछ समय बाद वही अधिकारी अपनी सेवा में पदोन्नित की सीढ़ियां चढ़ते हुए सर्वोच्च पदों तक चढ़ते हुए देखे गए हैं। जब किसी अधिकारी को भ्रष्ट तरीके अपनाने पर किसी प्रकार की तत्काल कड़ी सजा का डर नहीं होगा, तो विरले अधिकारी ही ईमानदारी की राह पर चलना पसंद करेंगे। आज यही त्रासदी सिविल सेवा के साथ में है। वे देखते हैं कि बेईमान अधिकारी, केवल चाटुकारिता के बल पर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि जनता के प्रति समर्पित ईमानदार अधिकारी कई बार सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों के कोप के भाजन बन जाते हैं। संवेदनहीन और बेईमान अधिकारियों को सजा देने के लिए यदि कानूनी प्रक्रिया में संशोधन की भी आवश्यकता हो तो, उसे करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। एक बार जब सही प्रकार के अधिकारी मिल गए, तो फिर बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी और जनता को उनकी अपेक्षा के अनुसार शासन व्यवस्था उपलब्ध हो पाएगी।

डेढ़ सौ करोड़ की जनसंख्या वाले देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यदि उनकी प्रगति में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वह स्वार्थ अथवा दबाव के कारण होती है। हमने हाल ही में अभी, सीबीएसई और नीट की परीक्षा में देखा है कि किस प्रकार अपने व्यक्तिगत लोभ के लिए लोग लाखों युवाओं का भविष्य दाँव पर लगा देते हैं।

अब देश और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अब तत्काल इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप अधिकारी सही रूप से चयन तक नहीं कर सकते, तो फिर जनता के साथ तो अन्याय ही होगा। उच्च अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु एक अलग से स्वतंत्र बोर्ड बनाया जाना चाहिए जो अधिकारियों को किसी भी पद पर काम करने के लिए न्यूनतम तीन साल का कार्यकाल दे।यदि निश्चित अवधि से पहले किसी का स्थानांतरण करना हो तो उसके लिए विशेष कारण अंकित करना अनिवार्य होना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में अधिकारियों को फुटबॉल की तरह एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की परिपाटी हो गई है।

उपरोक्त कुछ सुझाव लेखक ने अपने दीर्घ प्रशासनिक अनुभव और अब सेवानिवृत्ति के बाद समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चाओं के आधार पर दिए हैं। आशा है, लोक सेवा आयोग और सरकारें इस ओर गंभीरता से ध्यान देंगे ताकि देशवासियों को संवेदनशील और ईमानदार, जनहितकारी शासन मिल सके जिसके वे हकदार हैं।

**–राजेन्द्र भाणावत**
**( पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी )**

## राशिफल

**पंडित अनिल शर्मा**

**शुक्रवार 12 जून, 2026**

द्वितीय ज्येष्ठ मास (अधिक), कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2083, अश्विनी नक्षत्र प्रातः 6:29 तक, अतिगंड योग रात्रि 9:26 तक, कौलव करण प्रातः 9:07 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थितिः** सूर्य-वृष, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मेष, बुध-मिथुन, गुरू-कर्क, शुक्र-कर्क शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:29 तक है। राजयोग प्रातः 6:29 से योग रात्रि 7:37 तक है। आज प्रदोष व्रत है।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** चर सूर्योदय से 7:19 तक, लाभ अमृत 7:19 से 10:44 तक, शुभ 12:27 से 2:09 तक, चर 5:34 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:36, सूर्यास्त 7:17

**मेष**
मानसिक तनाव दूर होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। घर-परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

**वृष**
मित्रों/रिश्तेदारों के अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। पारिवारिक कारणों से भागदौड़ और मन में असंतोष बना रहेगा। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

**मिथुन**
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

**कर्क**
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

**सिंह**
धार्मिक-सामाजिक समारोह में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

**कन्या**
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना का भय है।

**तुला**
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

**वृश्चिक**
विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

**धनु**
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। व्यक्तिगत परेशानियां यथावत बनी रहेगी।

**मकर**
घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कुंभ**
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों से संबंधित विवादों का निपटारा हो सकता है।

**मीन**
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।